the Lok Sabha. [*See* appendix IX, annexure No. 8].

Sootia Railway Out-Agency

3483. Shri Bhagavati: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Sootia Railway Out-Agency was closed in January, 1960;

(b) whether Government have received any representations to re-open this Out-Agency; and

(c) if so, what is Government's decision thereon?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) It has been decided to open an Out-Agency at Chariali which would serve Sootia as well.

Hirakud Dam Project

3484. Shri Panigrahi: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the date from which the Orissa Government is required to start making repayment of the money invested in the construction of Hirakud Project;

(b) whether the Orissa Government has started making any repayment;

(c) whether repayment of capital money to the Centre will be on any annual instalment basis;

(d) if so, what is the annual instalment fixed;

(e) the amounts repaid towards capital money with interest so far separately; and

(f) the amount due from Orissa Government at present?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Hathi): (a) to (e). The first loan to the Government of Orissa for financing the construction of the Hirakud Dam Project (Stage I) was sanctioned by the Government of India in 1948-49. According to the financial arrangements agreed to between the Government of India and the State Government, the loan will bear interest at 4½ per cent per annum and unless any arrangement for earlier repayment is agreed to between the two Governments, the loan is repayable in one instalment at the end of 40 years i.e. in 1988-89. The interest on the loan is payable annually by the State Government but during the construction of the Project, interest charges are added to capital.

(f) Rs. 70·39 crores till 1957-58.

Projects in Andhra Pradesh

3485. Shri M. V. Krishna Rao: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the present stage of progress of the following projects of Andhra Pradesh;

(i) the Sileru Power Project;

(ii) the Vamsadhara Project; and

(b) when these projects are likely to be started?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Hathi): (a) (i) The proposals in regard to the first stage of the Upper Sileru Power Project have been finalised by the State Government and a project report has been prepared by them;

(ii) The proposal for undertaking detailed investigation of the Gudari site in Orissa for constructing a reservoir for the Vamsadhara Project in Andhra Pradesh was under the consideration of two State Governments for some time. The Government of Orissa have now agreed that the investigation of the site may be carried out by the Central Water and Power Commission. The Central Water and Power Commission have been asked to take up the investigation.

(b) Sileru Power Project has not yet been technically approved by the Advisory Committee on Irrigation and Power Projects. As regards Vamsadhara Project, the investigation will take some time before a Project report can be prepared.

It is too early yet to say when work on these Projects will be started.

शिमला में शीत गोदाम

३४८६. **श्री पदम देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमला में स्केटिंग रिंक के नीचे एक शीत गोदाम के निर्माण की जो योजना राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन थी, उस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): शिमला में स्केटिंग रिंक के नीचे द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कोल्ड स्टोरेज प्लान्ट (Cold Storage Plant) स्थापित करने के लिये योजना नहीं है।

चम्बा (हिमाचल प्रदेश) में भूमि का कटाव

३४८७. **श्री पदम देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ६ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बा में भूमि के कटाव को रोकने सम्बन्धी सात योजनाओं में से अब तक कितनी कार्यान्वित की जा चुकी हैं ;

(ख) वे योजनायें कहां कहां कार्यान्वित की गई हैं ; और

(ग) जिन स्थानों में भूमि के कटाव को रोकना असंभव हो गया है, क्या वहां के लोगों को कहीं अन्यत्र बसाने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) (क) छः योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं, लोअर चम्बा में चम्बा टाउन (Chamba Town Soil Erosion Scheme) सॉइल एरोज़न स्कीम नाम की एक योजना पर अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

(ख) कटौला खड, रावलसर झील और हमलेट्स, सरमौर रेंज, भंडल रेंज, सुकेत रेंज और बरोट के ऊपर के जलग्रहों में।

(ग) ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

हिमाचल प्रदेश को रासायनिक उर्वरक का संभरण

३४८८. **श्री पदम देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष १९५७-५८ में दिये गये उर्वरक की सम्पूर्ण मात्रा का वितरण किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितना उर्वरक अब भी वितरित किया जाना है ; और

(ग) उसका वितरण न करने का क्या कारण है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) जी नहीं।

(ख) २६० टन अमोनियम सल्फेट में से १५५ टन की मात्रा अभी वितरित नहीं की गई है।

(ग) (१) यूनियन टेरेट्रीज़ के प्रशासन द्वारा स्टाक का इन्डन्ट (Indent) किया गया था जिसमें से कुछ स्टाक रबी १९५७ के लिये और कुछ स्टाक खरीफ १९५८ के लिये था। इस समय पड़ा हुआ स्टाक चालू खरीफ मौसिम में इस्तेमाल करने के लिये है।

(२) दी हिमाचल प्रदेश कोआपरेटिव फडरेशन (The Himachal Pradesh Cooperative Federation) ने, जो कि पहले वितरण का काम कर रही थी, इस कार्य को न करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि उनको इस कार्य में पारिश्रमिक कम मिलता था। इस लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन को कोआपरेटिव